



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2015/पौष 7, 1937

No. 332]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2015/PAUSA 7, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/17/2015-डीजीएडी.—अतः घरेलू उद्योग की ओर से मै.यार्कशयर ट्रांसपोर्ट इन्क्रिपमेंट) इंडिया (प्रा.लि. (जिसे इसके बाद आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इससे आगे नियमावली भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसे बाद में प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलरों के लिए एक्सल' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और अतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई

परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

3. घरेलू उद्योग की ओर से मै.यार्कशायर ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा.लि.ने आवेदन दायर किया है।

4.आवेदक के दावों के अनुसार मै.यार्कशायर ट्रांसपोर्ट इन्क़िपमेंट (इंडिया) प्रा.लि.संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा भारतीय विनिर्माता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनियों का उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और संबंधित नियमावली के नियम (3)5 के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "ट्रेलरों के लिए एक्सल" है। "ट्रेलरों के लिए एक्सल" अनिवार्य रूप से एक बीम/छड़ एवं अन्य उपकरणों यथा ब्रेक ड्रम, ब्रेक शूज, वीयरिंग आदि को जोड़कर रखने का कार्य करता है, जो एक ट्रेलर के दो पहियों (व्हील) को जोड़ता है और यह ट्रेलर के लिए एक्सल के रूप में कार्य करता है। संबद्ध वस्तुओं का अलग-अलग किस्मों में विनिर्माण किया जाता है और बिक्री की जाती है। तथापि, इन सभी किस्मों की बुनियादी उत्पाद विशेषताएं और अंतिम उपयोग एक समान रहता है तथा ट्रेलर एक्सलों की सभी ऐसी किस्मों में विचाराधीन उत्पाद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं क्योंकि ये किस्मों एक समान विचाराधीन उत्पाद बनती हैं जो बुनियादी विशेषताओं और समान कार्यों/उपयोगों के साथ तुलनीय होती हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद वाहन का एक पुर्जा एवं सहायक उपकरण होता है, जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 और सीमा-शुल्क उप शीर्षक सं. 87169010 के अंतर्गत आता है। चूंकि उप शीर्षक एक पूर्णरूपेण वर्गीकरण नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया है कि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

तथापि, ट्रेलरों के अलावा वाहनों के एक्सलों को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाता है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुएं समान हैं। आवेदकों के निवेदन के अनुसार घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पादन और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं यथा वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। उपभोक्ता इन दोनों को परस्पर बदल कर उपयोग कर सकते हैं और उपयोग कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमों के अंतर्गत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी, भारत में आवेदकों के द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों/प्रान्तों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं की भांति "समान वस्तु" मानते हैं।

संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच चीन जनवादी गणराज्य ("संबद्ध देश" के रूप में निर्दिष्ट) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। आवेदकों ने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों

में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी अनुमान तथा चीन जनवादी गणराज्य के प्रक्रिया दिखाने वाले निर्यातकों द्वारा इसका खण्डन करने के अध्यक्षीन चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार अनुमान लगाया गया है।

निर्यात कीमत :

10. दूसरे स्रोतों अर्थात् आई बीआईएस से एकत्र किए गए सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया है। अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, क्रेडिट लागत, निर्यात करने वाले देश में बैंक प्रभारों के लिए फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्यों की फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत से तुलना की गई है। इस बात के लिए प्रथम दृष्टया काफी साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत अधिक है, जो यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश के निर्यातकों के द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन डी मिनिमस से अधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों के द्वारा दी गई सूचना के बारे में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने सापेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ती हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत में कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के फलस्वरूप क्षति होने तथा उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, माल सूची में गिरावट होने की वजह से काफी प्रतिकूल प्रभाव होने के संबंध में साक्ष्य दिए हैं। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" के बारे में प्रथम दृष्टया काफी साक्ष्य हैं।

जांच अवधि

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2015 (15 महीने) तक है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

16. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई करने हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. प्रश्नावली के उत्तरों/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के मामले में यह दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए - (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए।

19. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी के द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा गोपनीय वृत्तांतों की 2-2 प्रतियां और अगोपनीय वृत्तांतों की 5-5 प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों सहित प्रस्तुत करनी चाहिए।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है और/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु के समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, विषय परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक गोपनीयता रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है अथवा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए.के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2015

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR

No.14/17/2015-DGAD.—M/s Yorkshire Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. on behalf of domestic industry (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Axle for Trailers (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Yorkshire Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. on behalf of domestic industry.

4. As per the claims of the applicant M/s Yorkshire Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. is the largest Indian manufacturer of the subject goods. As per the evidence available on record, the production of the applicant companies constitutes "a major proportion" of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration in the present application is 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. An 'Axle for Trailer' is essentially an assemblage of a beam/bar and other components such as brake drum, brake shoes, bearings etc. which connects two wheels of a Trailer and renders the functions as axle for the Trailer.

The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles is covered in the scope of the PUC since these variants constitute a homogenous PUC with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

6. Product under consideration is a vehicle part and accessory, falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under custom sub-heading no. 87169010. Since the sub-heading is not a dedicated classification, the petitioner submitted that the customs classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope.

However, Axles for vehicles other than the Trailers are excluded from the scope of PUC.

Like Article

7. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore,

for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

Countries involved

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR (referred to as the "subject country").

Normal Value

9. Applicants have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy and determined normal value in accordance with Paras 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

10. Export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data collected from secondary sources i.e. IBIS. Adjustments have been made on account of inland freight, port expenses, ocean freight, marine insurance, commission, credit cost and bank charges in the exporting country to arrive at ex-factory export price.

Dumping Margin

11. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

12. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation (POI)

13. The period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2014 to 30th June 2015 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods April 2011-March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the period of investigation.

Submission of information

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version along with soft copies of both the versions must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K. BHALLA, Designated Authority